केन्द्र-हिमाचल की साझा कंपनी करेगी बिजलीघर का निर्माण, कोल लिंकेज नहीं बनेगी बाधा

बक्सर में बनेगी बिजली

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट क्षमता का बिजलीघर लगेगा। कोल लिंकेज की समस्या इसमें आड़े नहीं आएगी। इस बिजलीघर का निर्माण केन्द्र और हिमाचल सरकार की साझा कंपनी 'सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड' करेगी। सोमवार को राज्य कैबिनेट ने निर्माण की जिम्मेदारी इस कंपनी को सौंपने और त्रिपक्षीय समझौता करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिजलीघर के लिए कोल लिंकेज का इंतजाम यही कंपनी करेगी। राज्य को कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। इससे बिजली संकट में कमी आएगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी अवसर बढ़ेगा। कंपनी कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखेगी।

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने बताया कि बक्सर बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना में 660-660 मेगावाट की दो इकाइयों का निर्माण होना था। कंपनी परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करेगी। बिजली घर के लिए स्थल सर्वेक्षण, भू तकनीकी अनुसंधान, पर्यावरण प्रभाव और भूमि अधिग्रहण से संबंधित आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं। वाटर लिंकेज के लिए केन्द्रीय जल आयोग और चिमनी की ऊंचाई के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण से एनओसी लिया जा चुका है। लिहाजा एमओयू में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

कैबिनेट ने बिजली घर के लिए चौसा अंचल के मौजा बनारपुर में 2.72 एकड़ और मौजा बेचनपुरवा में लगभग एक एकड़ जमीन क्रमशः 36.72 लाख और 13.82 लाख रुपये की कीमत पर आधारभूत संरचना विकास निगम को सौंप दिया है।

● खर्च होंगे तीन अरब रुपए पेज-07

राज्य कैबिनेट का फैसला

1320 मेगावाट क्षमता का होगा बिजलीघर

15% हिस्सा कंपनी अपने पास रखेगी

85% बिजली राज्य को परियोजना से मिलेगी

नई कंपनी सुधारेगी ट्रांसमिशन प्रणाली

बिजली की ट्रांसमिशन प्रणाली को अब एक नई कंपनी दुरुस्त करेगी। सोमवार को कैबिनेट ने बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम होगी। इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच 25 वर्षीय समझौता हुआ है।

'नीचे मछली, ऊपर बिजली' परियोजना

'नीचे मछली, ऊपर बिजली' परियोजना की बिजली बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड खरीदेगी। राज्य सरकार कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। राज्य के जलजमाव वाले इलाकों में 'नीचे मछली, ऊपर बिजली' परियोजना में सौर ऊर्जा के माध्यम से 150 मेगावाट और सामान्य इलाकों में 100 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।